भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1854
11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई का कार्यान्वयन

1854. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन किस हद तक किया जा रहा है तथा अब तक इस दिशा में विशेष रूप से स्थानीय मत्स्यपालन अवसंरचना और आजीविका में सुधार के संदर्भ में क्या प्रगति हुई है;
(ख) पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन क्षेत्र के जिन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जैसे अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुंच का ब्यौरा क्या है;
(ग) इन पहलों को झालावाड़-बारां और राजस्थान के अन्य भागों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप किस हद तक तैयार किया जा रहा है; और
(घ) परिवहन, शीत भंडारण और बाजार संपर्क जैसे मुद्दों के समाधान सहित राजस्थान के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत किस हद तक पहलों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत 2372.65 लाख रुपए के केंद्रीय अंश के साथ कुल 7095.14 लाख रूपए की लागत पर राजस्थान सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में जलाशयों में 486 केज की स्थापना, दो फ्रेशवॉटर फिनफिश हैचरी की स्थापना, 60 हेक्टेयर में इनपुट लागत के साथ ग्रो-आउट पॉण्ड, 110 हेक्टेयर में इनपुट के साथ खारे-क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाब, दो बायोफ्लोक, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) की 3 इकाइयां, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की 9 इकाइयां (रेफ्रिजरेटेड ट्रक, इंसुलेटेड ट्रक, आइस बॉक्स के साथ थ्री व्हीलर/मोटरसाइकिल), एक कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट, फीड मिल आदि शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत झालावाड़ और बारां जिलों में केज कल्चर गतिविधियों और तालाबों में मत्स्यपालन के लिए सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, स्थानीय मछुआरों के लाभ के लिए राजस्थान के चुरू जिले में एक्वाकल्चर फ़ार्मिंग प्रैक्टिसेस पर एक प्रदर्शन और प्रशिक्षण इकाई को कुल 53.32 लाख रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है।

******